दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, शुक्रवार 27 अगस्त 2021 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-03, अंक- 327

ग्रीन जोन में ड्रोन उड़ाने के लिए किसी मंजूरी की जरूरत नहीं

» केंद्र सरकार नई ड्रोन नीति का किया सरलीकरण

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश की सीमा पर आजकल सुरक्षा से लेकर मौसम विज्ञान, आपदा प्रबंधन, सर्वेक्षण, खेती-किसानी से लेकर, सामान डिलीवरी और फोटोग्राफी तक में ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। आने वाले समय में ड्रोन की उपयोगिता को देखते हुए केंद्र सरकार ने नई ड्रोन नीति का एलान किया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि ड्रोन संबंधी नए नियमों से भारत में इस क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक क्षण की शुरुआत हो गई है। उन्होंने यह भी कहा कि ड्रोन संबंधी नए नियमों से स्टार्ट-अप्स के साथ-साथ इस सेक्टर में काम करने वाले हमारे युवाओं को भी काफी मदद मिलेगी। नई नीति की जरूरत इसलिए थी क्योंकि अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों जैसे कृषि, खनन, आधारभूत संरचना, निगरानी, आपातकालीन परिस्थितियों, परिवहन, मानचित्रण, रक्षा और कानून प्रवर्तन एजेंसी को ड्रोन से जबरदस्त लाभ मिल रहा है और आने वाले दिनों में इसका इस्तेमाल और बढ़ना है। कई देश की सेना ने अपनी सीमा सुरक्षा के लिए ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ा दिया है। नवाचार, सूचना प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग में इसके बढ़ते इस्तेमाल और विशाल घरेलू मांग को देखते हुए यह माना जा रहा है कि भारत 2030 तक वैश्विक ड्रोन हब बन सकता है। ड्रोन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ड्रोन प्रोत्साहन परिषद की स्थापना करने की भी तैयारी कर रही है।

क्या है नई ड्रोन नीति- नई ड्रोन नीति के मुताबिक सभी ड्रोन का ऑनलाइन पंजीकरण होगा। अब पंजीकरण,लाइसेंस के लिए सुरक्षा मंजूरी लेने और ड्रोन के रखरखाव का प्रमाणपत्र देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माइक्रो ड्रोन (गैर-व्यावसायिक उपयोग के लिए) और नैनो ड्रोन के लिए रिमोट पायलट लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी।

कार्गो डिलिवरी के लिए कॉरीडोर बनाए जांएगे। डीजीसीए ड्रोन प्रशिक्षण आवश्यकताओं को देखेगा और ऑनलाइन पायलट लाइसेंस जारी करेगा। ड्रोन उड़ाने के लिए प्रशिक्षण और परीक्षा ड्रोन स्कूलों में होगी। रिमोट पायलट लाइसेंस शुल्क का शुल्क तीन हजार रुपये (बड़े ड्रोन के लिए) से कम करके सभी श्रेणियों के लिए 100 रुपये कर दी गई है और यह 10 साल के लिए वैध है। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म को उपयोगकर्ता के अनुकूल सिंगल-विंडो सिस्टम को विकसित किया जाएगा। जिसमें कम से कम मानव दखल होगा। नए नियमों के तहत ड्रोन का अधिकतम वजन 300 किलोग्राम से बढ़ाकर 500 किलोग्राम कर दिया गया है। इससे ड्रोन टैक्सियों को भी ड्रोन नियमों के दायरे में लाना आसान होगा। वैसे सरकार ने जुलाई ही में ड्रोन नियम 2021 की घोषणा की थी। यह नियम अब 12 मार्च को जारी मानव रहित विमान प्रणाली नियम 2021 की जगह लेगा। दरअसल यह नियम अकादमिक, स्टार्टअप्स, उपयोगकर्ता और अन्य हितधारकों ने बहुत प्रतिबंध करने वाला लगा था, क्योंकि इसमें काफी कागजी कार्रवाई की जरूरत थी और हर ड्रोन उड़ाने के लिए आवश्यक अनुमति चाहिए थी।

देश में फिर बढ़े कोरोना के नए मामले

» पिछले 24 घंटे में 46,164 नए मरीज, 607 की मौत

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश में कोरोना की तीसरी लहर संकेत देती नजर आ रही है। दूसरी लहर का पीक निकलने के तीन महीने बाद भी बढ़ते संक्रमण के मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। पिछले एक दिन में 46,164 नए मामले दर्ज किये गये, जबकि 607 लोगों की मौत हो गई। मसलन पिछले दो दिन में लगातार 20 हजार से भी ज्यादा दैनिक मामले बढकर सामने आए हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार गुरुवार को बीते 24 घंटे में कोरोना के 46,164 नए मामले आने के बाद देश में अब तक आए हैं। जबकि 607 लोगों की मौत के बाद अब तक संक्रमण से देश में 4,36,365 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इस दौरान 34,159 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं, जिसके बाद अब तक देश में

उपचार के बाद 3,17,88,440 लोगों ने कोरोना को मात दी है। अब देश में सक्रीय मरीजों की संख्या 3,33,725 है, जिनका इलाज चल रहा है। एक दिन पहले बुधवार को बुधवार को कोरोना के 37,593 नए मामले आए थे, जबकि 648 लोगों की मौत हो गई थी और 34,169 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट गए थे।

केरल में फिर बेकाबू हुई कोरोना की रफ्तार - केरल में गुरुवार को बीते 24 घंटे में कोरोना के 31445 नए मामले सामने आए हैं। जिससे राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 38,83,429 हो गई। जबकि 215 और मरीजों की मौत होने से मृतकों की तादाद 19,972 पर पहुंच गई।

महत्वपूर्ण एवं खास

छत्तीसगढ़ के दो दिवसीय दौरे पर आज आयेंगे अर्जुन मुण्डा

नईदिल्ली (आरएनएस)। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा जनजातीय सशक्तिकरण के लिए संचालित कार्यक्रमों जैसे; एमएफपी, वीडीवीके और ट्राईफूड के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए शुक्रवार को छत्तीसगढ़ राज्य के दो दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। उनके साथ ट्राइफेड के प्रबंध निदेशक प्रवीर कृष्ण और जनजातीय कार्य मंत्रालय और ट्राइफेड के वरिष्ठ अधिकारी भी होंगे। इस दो दिवसीय दौरे के दौरान मुंडा रायपुर में राज्य के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे।इसके बाद वे बस्तर जिले का दौरा करेंगे और जगदलपुर में बन रहे ट्राईफूड फूड पार्क का भ्रमण करेंगे।वे वन धन प्राकृतिक पुरस्कार समारोह में जनजातीय लाभार्थियों के साथ आमने-सामने बातचीत भी करेंगे औरउनकी कुछ उत्कृष्ट उपलब्धियों को भी मान्यता देंगे। अर्जुन मुंडा जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ धुरागांव वीडीवीकेसी का भी दौरा करेंगे और जनजातीय लाभार्थियों यानीवन संग्रहकर्ताओं और कारीगरों, दोनों के साथ बातचीत करेंगे। इस दौरे के दौरान, केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री व्यक्तिगत रूप से इन जनजातीय विकास योजनाओं के जमीनी स्तर के कार्यान्वयन, चुनौतियों और प्रगति की समीक्षा व मूल्यांकन करेंगे।इन कार्यक्रमों का मूल उद्देश्य पूरे देश में जनजातीय जीवन व आजीविका के एक पूर्ण बदलावपर प्रभाव डालना और एक आत्मानिर्भर भारत की दिशा में प्रगति करना है।

टीएमसी सांसद एवं अभिनेत्री नुसरत जहां बनीं मां, बेटे को दिया जन्म

नईदिल्ली (आरएनएस)। तृणमूल कांग्रेस की सांसद और अभिनेत्री नुसरत जहां मां बन गयी हैं। उन्होंने बेटे को जन्म दिया है। इस खबर के बाद फैन्स के साथ-साथ कई सेलिब्रेटी भी उन्हें बधाई संदेश दे रहे हैं। नुसरत जहां की डिलिवरी पार्क स्ट्रीट स्ट्रीट स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में हुई। बच्चे के जन्म के बाद नुसरत और बेटा दोनों स्वस्थ हैं। अस्पताल में उनका ख्याल रखने के लिए अभिनेता यश दासगुप्ता मौजूद थे।

ड्रोन संबंधी नये नियमों से स्टार्टअप और इस क्षेत्र में काम कर रहे युवाओं को अत्यधिक मदद मिलेगी

नईदिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि ड्रोन संबंधी नए नियमों से भारत में इस क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक क्षण की शुरुआत हो गई है। उन्होंने यह भी कहा कि ड्रोन संबंधी नए नियमों से स्टार्ट-अप्स के साथ-साथ इस सेक्टर में काम करने वाले हमारे युवाओं को भी काफी मदद मिलेगी। उन्होंने ट्वीट में कहा कि 'ड्रोन संबंधी नए नियमों से भारत में इस क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक क्षण की शुरुआत हो गई है। ये नियम विश्वास और स्व-प्रमाणन की अवधारणा पर आधारित हैं। इसके तहत अनुमोदन एवं अनुपालन से संबंधित आवश्यकताओं और इस क्षेत्र में प्रवेश करने संबंधी बाधाओं को काफी हद तक कम कर दिया गया है। ड्रोन संबंधी नए नियमों से स्टार्ट-अप्स के साथ-साथ इस सेक्टर में काम करने वाले हमारे युवाओं को भी काफी मदद मिलेगी। इससे नवाचार और कारोबार के लिए संभावनाओं के नए द्वार खुल जाएंगे। इससे भारत को एक ड्रोन हब बनाने के लिए नवाचार, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग में भारत की विशिष्ट क्षमताओं का व्यापक उपयोग करने में भी काफी मदद मिलेगी।'

जमीन विवाद को लेकर गोलीबारी, आठ लोगों की मौत

पेशावर। पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिम खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में भूमि विवाद को लेकर दो प्रतिद्वंद्वी समूहों के बीच हुई गोलीबारी में आठ लोगों की मौत हो गई और 12 अन्य घायल हुए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने यह जानकारी दी। प्रांत के लोअर कुर्रम कबायली जिले में दो गुटों के बीच यह गोलीबारी हुई। पुलिस ने कहा कि दोनों समूहों के बीच बातचीत के बाद गोलीबारी बंद हो गई है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में शांति कायम करने के प्रयास जारी हैं।

ब्लैक फंगस की जांच के लिए बाजार में आई स्वदेशी किट

» पश्चिम बंगाल के वैज्ञानिकों ने तैयार किया उपकरण

नई दिल्ली (आरएनएस)। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में वैज्ञानिकों ने ब्लैक फंगस होने वाले मरीजों की जांच के लिए स्वदेशी किट विकसित की है। दक्षिण 24 परगना के बकराहाट क्षेत्र की एक लैब में वैज्ञानिकों ने इसे तैयार किया है। इस किट की कीमत एक हजार रुपये होगी। इससे पहले यह इससे सात से आठ हजार रुपये में खरीदना पड़ता था। किट तैयार करने वाली कंपनी जीसीसी बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक राजा मजूमदार ने बताया कि बाजार में पहले 7,000-8000 रुपये में किट उपलब्ध थी, लेकिन नई तकनीक की वजह से इसकी कीमत में गिरावट आई है। अब यह 1000 रुपये में उपलब्ध है। यह ब्लैक फंगस टेस्ट किट बनाने वाली देश की पहली कंपनी है। दुनिया में अभी तक इससे सस्ती किट बनाने वाली कोई कंपनी नहीं है। कलकत्ता विश्वविद्यालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के प्रोफेसर कौस्तव पांडा के मुताबिक, यह परीक्षण किट 95 फीसद बलगम या फंगस की पहचान करने में कामयाब है। इनमें मुख्यत: तीन तरह के फंगस होते हैं। जबकि आयातित किट 65 फीसद बलगम या फंगस की पहचान कर सकती है।

देश की पहली महिला सीजेआई बनने का रास्ता साफ

» राष्ट्रपति ने कॉलेजियम के 9 नामों पर लगाई मुहर

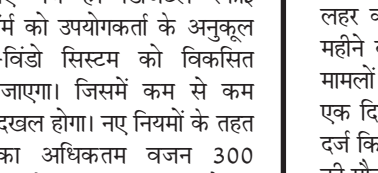

नईदिल्ली (आरएनएस)। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम कि अनुशंसा वाले सभी नौ नामों को मंजूरी दे दी है. नौ नामों में आठ जज और सुप्रीम कोर्ट के एक वकील शामिल हैं. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्तियों के लिए सीजेआई एन.वी. रमना के नेतृत्व वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा भेजे गए सभी नामों को मंजूरी दी गई है. इसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सुप्रीम कोर्ट के नौ जजों की

नियुक्ति को मंजूरी दे दी है. इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है.

इन नामों में से एक न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना हैं, जो भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में हो सकती हैं. माना जा रहा है कि फाइलों को आगे की औपचारिकताओं और नियुक्तियों के लिए राष्ट्रपति को भेज दिया गया है. अगर सब कुछ सही होता है तो सुप्रीम कोर्ट में जल्द नौ नए न्यायाधीश शपथ लेंगे.

नौ नामों में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के आठ जज और एक वकील शामिल हैं. इनमें कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश ए.एस. ओका भी हैं, जो सभी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों में सबसे वरिष्ठ मुख्य न्यायाधीश हैं. गुजरात के मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ, सिक्किम के मुख्य न्यायाधीश जे.के. माहेश्वरी, तेलंगाना की मुख्य न्यायाधीश हिमा कोहली भी इस लिस्ट में शामिल हैं. हिमा कोहली हाईकोर्ट की एकमात्र सेवारत महिला मुख्य न्यायाधीश भी हैं.

केरल हाईकोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति नागरत्ना, मद्रास हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सी.टी. रवि कुमार, न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश, न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी और वरिष्ठ अधिवक्ता पीएस नरसिंह का नाम सिफारिश में शामिल था. कॉलेजियम में सीजेआई के अलावा जस्टिस यू.यू. ललित, ए.एम. खानविलकर, डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव की बैठक 17 अगस्त को हुई थी.

तालिबान ने देश चलाने को दुनिया से लगाई आर्थिक मदद की गुहार

» भारत के लिए भी भेजा संदेश

नई दिल्ली (आरएनएस)। 20 साल बाद अफगानिस्तान में दोबारा वापसी करने वाला तालिबान कितना उदार होगा और कैसे देश चलाएगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर अभी से ही उसने संकेत दे दिए हैं कि अन्य मुल्कों के साथ वह किस तरह का संबंध रखने वाला है। बीते सप्ताह काबुल पर कब्जा करने के बाद भी तालिबान सरकार बनाने की कोशिशों में जुटा है। इस बीच उसने अंतराष्ट्रीय समुदाय से आर्थिक मदद की अपील की है। साथ ही उसने भारत के लिए भी एक संदेश भेजा है जो काफी अहम है।

तालिबानी प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने

कहा कि अगर भारत की परियोजनाएं अफगानिस्तान में अधूरी हैं तो वे इसे पूरा कर सकते हैं। दरअसल, जब यह पूछा गया कि भारत ने पिछले दो दशकों में अफगानिस्तान के विकास में भारी निवेश किया है। भारत ने सड़कों, बांधों और यहां तक कि संसद भवन का भी निर्माण किया है। मगर यह बताया जा रहा है कि तालिबान ने भारत के साथ व्यापार बंद कर दिया है। क्या यह सच है और क्या यह स्थायी है? इस पर प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा कि उनकी (भारत की) परियोजनाएं, जो अफगानिस्तान के लोगों के लिए अच्छी हैं और जो अफगानिस्तान के लोगों के कल्याण में योगदान करती हैं, अगर वे अधूरी हैं तो वे इसे पूरा कर सकते हैं। आतंकी संगठन तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि हम जिस चीज का विरोध कर रहे हैं, वह यह है कि भारत गनी सरकार का पक्ष लेता रहा है। हम पिछले 20 साल से यही चाहते हैं कि भारत समेत सभी देशों का संबंध अफगानिस्तान के लोगों से हो और उन्हें अफगानिस्तान के लोगों की मंशा को भी स्वीकार करना चाहिए। यही हमारी बात और हमारी स्थिति थी और हमने हमेशा कहा है कि किसी को भी उस कठपुतली सरकार (गनी सरकार) का पक्ष नहीं लेना चाहिए। उन्हें अफगानिस्तान के लोगों का समर्थन करना चाहिए।

अफगानिस्तान में विकास कार्यों में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भागीदारी को लेकर आपका क्या संदेश है, इस पर तालिबानी प्रवक्ता ने कहा कि उनके लिए मेरा संदेश है कि हमने अभी-अभी युद्ध समाप्त किया है और हम उस अध्याय को पीछे छोड़ रहे हैं। यह एक नया अध्याय है और अफगानिस्तान के लोगों को मदद की जरूरत है। अफगानिस्तान के लोगों को उनके जीवन के निर्माण और अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए सभी देशों को आर्थिक रूप से मदद करनी चाहिए। फिर हमारे अन्य देशों के साथ भी अच्छे संबंध होंगे। अफगानिस्तान के लोगों की मदद के लिए आगे आना उनकी मानवीय मजबूरी भी है क्योंकि 70 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे हैं। इसके अलावा, हमारे पास 20 साल का युद्ध और रक्तपात है।

सीआईडी ने पकड़ा 4250 करोड़ कीमत का दुर्लभ रेडियो एक्टिव मेटल, 2 गिरफ्तार

कोलकाता (आरएनएस)। कोलकाता एयरपोर्ट पर सीआईडी ने 4250 करोड़ रुपए मूल्य रेडियोएक्टिव मेटल कैलिफोर्नियम जब्त किया है. कोलकाता एयरपोर्ट क्षेत्र से महंगी रेडियोधर्मी धातु कैलिफोर्नियम के साथ सीआईडी ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है. गुरुवार को सीआईडी ने एक विश्वसनीय स्रोत सूचना पर कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में शैलेन कर्मकार (41 वर्ष), आनंदनगर के लेफ्टिनेंट बिस्वनाथ कर्माकर के पुत्र और सिंगूर, हुगली के निवासी हैं, जबकि दूसरा आरोपी असित घोष (49 वर्ष) भी हुगली के ही निवासी है.

सीआईडी ने उनके पास से राख के रंग के पत्थरों के चार टुकड़े मिले, जिनका वजन लगभग 250.5 ग्राम था. वे अंधेरे में पत्थर चमक रहे थे और उन पत्थरों से रोशनी परावर्तित हो रही थी. पत्थरों को देखकर ऐसा लगता है कि यह खनिजों से भरा हुआ था.

प्रारंभिक जांच के दौरान यह पता चलता है कि जब्त की गई वस्तुएं कैलिफ़ोर्नियम हो सकती हैं, जो कि इंटरनेट स्रोत के अनुसार एक रेडियो सक्रिय धातु है. कैलीफोर्नियम की कीमत भारतीय मुद्रा के अनुसार 17 करोड़ रुपये प्रति ग्राम है.

राष्ट्रपति के कार्यक्रम में दो डीआईजी, 13 एसपी समेत 2500 पुलिसकर्मी, पीएसी, पैरा मिलिट्री फोर्स रहेगी तैनात

» होटल, सराय, ढाबा की चेकिंग शुरू, एयरफोर्स से लेकर कार्यक्रम स्थल तक रहेंगे सीसीटीवी कैमरे

» सुरक्षा प्लान चाक-चौबंद

गोरखपुर (आरएनएस)। राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा प्लान चाक-चौबंद रहेगी जिसके लिए एनेक्सी भवन सभागार में अन्य जनपदों से आए हुए राजपत्रित अधिकारियों के साथ एडीजी जोन अखिल कुमार ने ब्रीफ कर आवश्यक

दिशा निर्देश दिया। 26 अगस्त बृहस्पतिवार को सभी राजपत्रित अधिकारी पिपरी भटहट व सोनबरसा तथा एयरपोर्ट ड्यूटी लगाए हुए स्थानों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेकर बृहस्पतिवार को होने वाली ब्रीफिंग में संबंधित अधिकारी को अवगत कराएंगे जिससे उन कमियों को दूर किया जा सके पुनः सभी राजपत्रित अधिकारियों की बैठक एनेक्सी सभागार में 27 अगस्त शुक्रवार को ली जाएगी सुरक्षा व्यवस्था ऐसी की गई है कि चिड़िया पर ना मार सके। कोई भी बिना पास राष्ट्रपति के कार्यक्रम के दौरान नहीं आ जा सकता है संबंधित राजपत्रित अधिकारी अपने अधीनस्थ समस्त कर्मचारियों को गाइड करते हुए निर्देशित देंगे मंगलवार को मुख्य सचिव शासन ने भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुरक्षा का जायजा लिया था ।आज सुरक्षा मुख्यालय से अफसर गोरखपुर पहुंच गए। गोरखपुर जिले को हाई अलर्ट पर कर सुरक्षा और जांच तेज कर दी गई है। पुलिस वालों की नाम से ड्यूटी लगाई गई है और उनका आईकार्ड भी तैयार कर लिया गया है। राजपत्रित अधिकारियों को बुकलेट दे दिया गया है बुकलेट में आदेश निर्देश अवगत कराए गए हैं संबंधित को अनुपालन करना है होटल, सराय, ढाबा की चेकिंग बड़ा दिया गया है सुरक्षा में दो डीआईजी, 13 एसपी, 55 सीओ समेत भारी फोर्स लगाई गई है।

एयरफोर्स से लेकर कार्यक्रम स्थल तक पुलिस की चौकस व्यवस्था रहेगी। हर जगह सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा मानकों की जांच के लिए सुरक्षा मुख्यालय के अफसर भी कार्यक्रम के दो दिन पहले गोरखपुर आ जाएंगे। सुरक्षा में लगे राजपत्रित अधिकारियों को एनेक्सी भवन सभागार में ब्रीफिंग की गई अन्य जवानों को आज एक ब्रीफिंग की गयी। मंगलवार को एडीजी अखिल कुमार और कमिश्नर रवि कुमार एनजी ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया था। इसके अलावा लखनऊ से मुख्य सचिव शासन के वीडियो कांफ्रेंसिंग में भी एडीजी मौजूद थे। एडीजी अखिल कुमार ने बताया कि सुरक्षा का प्लान तैयार कर लिया गया है। सभी के आईकार्ड बनाए गए हैं। मुख्यालय के अफसर 26 को गोरखपुर आ जाएंगे। इसके अलावा चिलुआताल के आसपास एनडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया है। गोताखोर भी मौजूद रहेंगे।डीआईजीः 2 एसपीः 13 एडिशनल एसपीः 15 पैरामिलिट्री फोर्सः 5 कंपनी पीएसीः 10 कंपनी पुलिसकमीः 2500 ड्यूटी करेंगे अगर आवश्यकता पड़ेगी तो और जवानों को लगाया जा सकता है। ब्रीफिंग के दौरान एडीजी जोन अखिल कुमार डीआईजी गोरखपुर परिक्षेत्र गोरखपुर जे रविंद्र कुमार गौड़ कमिश्नर रवि कुमार एनजी जिलाधिकारी विजय किरन आनंद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ विपिन ताडा पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार सहायक पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक रामसेवक गौतम पुलिस अधीक्षक अपराध डॉक्टर एमपी सिंह पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी सहित अन्य जनपदों से आए हुए डीआईजी एसपी सीओ मौजूद रहे।